

कृषि विभाग, भारत सरकार पचनशील - शाकसब्जि ओ फलमूल, कृषि बीज, कीटनाशक एवंग सार इत्यादिर आन्तराष्ट्रीय चलाचलर जन्य राज्यगुलर मध्ये समन्वयर जन्य एकटि अल इन्डिया एग्रि ट्रांसपोर्ट कल सेंटर चालु करेहे

कल सेंटर नम्बर (टोल फ्री):

**18001804200 एवंग
14488**

एइ नम्बरगुलि ये कौनओ मोबाइल फोन वा ल्यान्डलाइन फोन थेके कल करा येते पारे।

ट्रक ड्राइवर, व्यवसायी, खुचरा व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर वा अन्य ये कौनओ स्टैकहोल्डर याँरा उपरर पण्यगुलर आन्तराष्ट्रीय चलाचले समस्याय पड़हेन, तारा एइ नम्बरगुलिते कल करे साहाय्य चाहते पारेन। कल सेंटर एलिक्ट्रिकिटीगुलि प्रयोजनीय सहायता सह यानवाहन एवंग चालानेर विवरणगुलि समस्यार समाधानेर जन्य राज्य सरकारेर कर्मकर्तारदर काहे प्रेरण करबेन।

आपनि एइ वार्ता सवार साथे शेयार करुन याते आरोग वेशि मानुष जन एइ विषये जानते पारेन।

कृषि विभाग, भारत सरकार ने राज्यों के बीच अंतर-राज्य यातायात के लिए ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर शुरू किया है - सब्जियां और फल, कृषि इनपुट जैसे बीज, कीटनाशक और उर्वरक आदि का।

कॉल सेंटर नंबर (टोल फ्री):

**18001804200 और
14488**

ये नंबर किसी भी मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन से लिए जा सकते हैं।

ट्रक चालक, व्यापारी, खुदरा विक्रेता, ट्रांसपोर्टर या कोई भी अन्य हितधारक जो उपरोक्त वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। कॉल सेंटर के अधिकारियों को वाहन और खेप के विवरणों को अग्रिष्ठित करना होगा-साथ ही, मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को आवश्यक मदद।

आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं।

Department of Agriculture, Govt Of India has started an All India Agri Transport Call Centre for coordination between States for inter state movement of perishables - Vegetables & Fruits, Agri Inputs like seeds, pesticides and fertilizer etc.

Call Centre Number (toll free):

**18001804200 and
14488**

These numbers can be called from any mobile phone or landline phones.

Truck drivers, Traders, Retailers, Transporters or any other stakeholders who are facing problems in inter-state movement of above commodities, may seek help by calling at these numbers. Call Center Executives will forward the vehicle & consignment details along-with the help needed, to State Government officials for resolution of issues.

You may share with all.